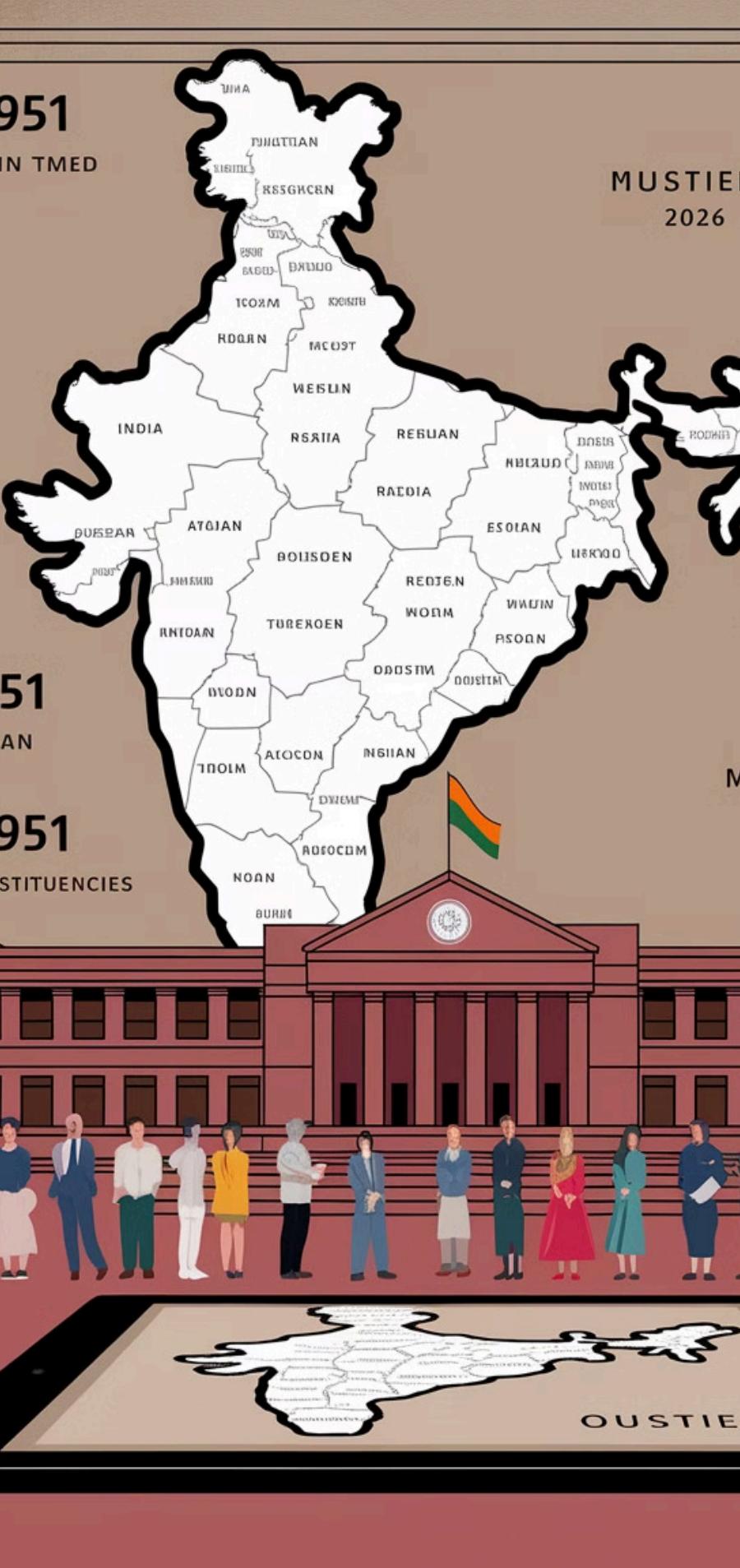


जनसंख्या गणना से परे सोचना: राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक नया दृष्टिकोण

सीमांकन और वित्तीय विकेंद्रीकरण पर चर्चा ने संसद और कुछ राज्य विधानसभाओं में हँगामा मचा दिया है, जिससे हमारे राष्ट्र के संघीय स्वरूप को खतरा पैदा हो गया है। संसदीय सीटों पर संवैधानिक टोक जल्द ही समाप्त होने वाली है, जिससे प्रायद्वीपीय राज्यों और उत्तर के राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बढ़ती चिंता है।

भारत में विकास का अंतर एक जनसांख्यिकीय अंतर पैदा कर रहा है, जिसे सीमांकन और वित्तीय विकेंद्रीकरण की गणना में मान्यता देने की जड़त है। यह प्रस्तुति इस बात का पता लगाती है कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एकमात्र मानदंड के रूप में जनसंख्या आकार से आगे बढ़ना क्यों चाहिए और भारत के विविध राज्यों में संतुलित प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं।





भारत में सीमांकन का ऐतिहासिक संदर्भ

1

1951

लोक सभा सीट पर 7.3 लाख की आबादी

2

1951-1971

जनसंख्या वृद्धि के प्रतिक्रिया में सीटों में वृद्धि

3

1971

543 सीटों तक पहुंच गया, प्रति सीट 10.1 लाख की आबादी

4

1971-2026

संवैधानिक ढंप से सीटों की संख्या पर टोक

भारत में सीमांकन का इतिहास जनसंख्या वृद्धि के अनुकूल संसदीय सीटों में वृद्धि का पैटर्न दिखाता है। 1951 से 1971 तक, लोक सभा सीट पर जनसंख्या प्रतिनिधित्व 7.3 लाख से बढ़कर 10.1 लाख हो गया, कुल मिलाकर वर्तमान 543 सीटों तक पहुंच गया। यह संख्या 1971 से जमी हुई है, और यह टोक 2026 तक बढ़ी हुई है।

जनसंख्या-आधारित सीमांकन के प्रक्षेपित प्रभाव

753

प्रक्षेपित सीटें

2026 की जनसंख्या के अनुकूल कुल
लोक सभा सीटें

20 लाख

प्रति सीट जनसंख्या

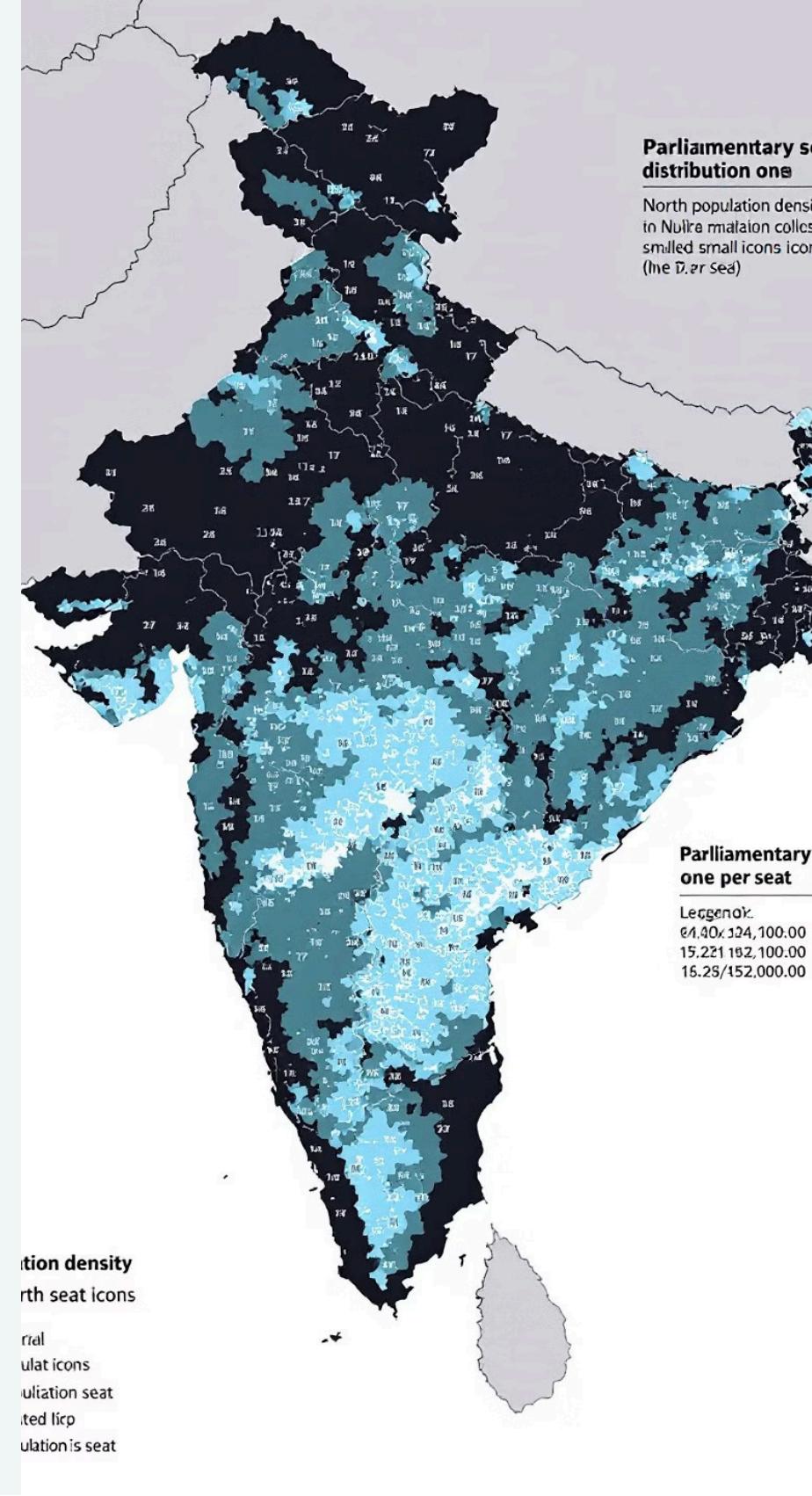
2026 तक प्रक्षेपित प्रतिनिधित्व
अनुपात

543

वर्तमान सीटें

1971 से जमे हुए कुल सीटें

जनसंख्या में वृद्धि के ऐतिहासिक ठङ्गानों का अनुसरण करते हुए, 2026 तक लोक सभा की कुल सीटें 753 तक पहुंच जाएंगी, जिसमें लगभग 20 लाख लोग प्रति सीट होंगे। यह एक चिंताजनक असंतुलन पैदा करता है: उत्तरी राज्यों की तुलना में जनसांख्यिकीय प्रगति बेहतर करने वाले प्रायद्वीपीय राज्य प्रतिनिधित्व खो सकते हैं।



UPSC 2026-2027

Current Affairs “SURE”

**HWC Method
(Selection wali class)**

Bilingual (हिंदी and English)

Online Batch



1 साल का बैच लेने पर **Rs.12,000**
की छूट!

Rs. 12,000 / Year ~~Rs. 24,000~~
Rs. 2,000 / Month

Call- 8750711100/22/33/44/55



By Ojaank Sir

🔥 UPSC को पक्का Current Affairs Strategy के साथ CRACK करना चाहते हो?
तो यह है आपकी Golden Navratri Opportunity 🕯️

Ojaank Sir की HWC Method = “Selection wali class” वापस आ गई है 2026-27 Aspirants के लिए 🚀

💥 Bilingual Batch (Hindi + English) 💥 Best से Best Online सीखने का मौका 💥 Navratri पर जबरदस्त छूट – ₹24,000 → अब सिर्फ ₹12,000/साल 💥 Monthly Payment? सिर्फ ₹2,000!

💡 Updated रहो, आगे बढ़ो, और IAS बनने का सपना सच करो 😊 Download Ojaank App Now Link :-
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ojaank>

Course Link - <https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/528>

📣 Limited Seats | पहले आओ पहले पाओ

Ojaank IAS में Admission लेने लिए दिए गए link पर Click करके Form भरें -

<https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmx/edit>

अधिक जानकारी के लिए तुरंत Call करें :- 8750711100/22/33/44/55

👉 Ojaank Sir के साथ सीधा Whatsapp से जुड़ें : 8285894079

वित्त आयोग का संतुलन का कार्य



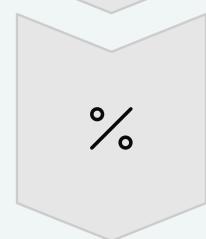
15वें वित्त आयोग की चुनौती

जनसंख्या वजन को 1971 से 2011 के आंकड़ों में अपडेट करने पर प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता थी



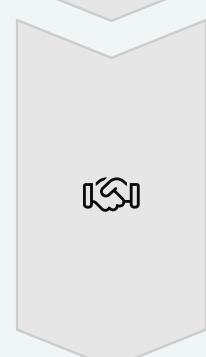
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन जोड़ना

जनसंख्या गणना के साथ-साथ जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को भी वजन देने का सुझाव दिया



वजन समायोजन

जनसंख्या घटक का वजन 0.15 से बढ़ाकर 0.27 कर दिया



संतुलन तंत्र

उच्च जनसंख्या/खराब जनसांख्यिकीय वाले राज्यों और कम जनसंख्या/बेहतर जनसांख्यिकीय वाले राज्यों के बीच संतुलन बनाया

15वां वित्त आयोग ने जनसंख्या गणना के साथ-साथ जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को भी शामिल करके एक समाधान पेश किया। जनसंख्या घटक का वजन 0.15 से बढ़ाकर 0.27 कर देने और जनसांख्यिकीय प्रगति को ध्यान में रखने से, राज्यों में संसाधनों के आवंटन के लिए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण बना।



जनसंख्या आकार से परे: वैकल्पिक दृष्टिकोण

जनसंख्या घनत्व

निबधि संख्या के बजाय घनत्व का उपयोग करना शहरी केंद्रों और उत्तर-पूर्व जैसे कम आबादी वाले क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसके पास पहले से ही अनुपातिक रूप से अधिक सीटें हैं।

अनुपातिक आवंटन

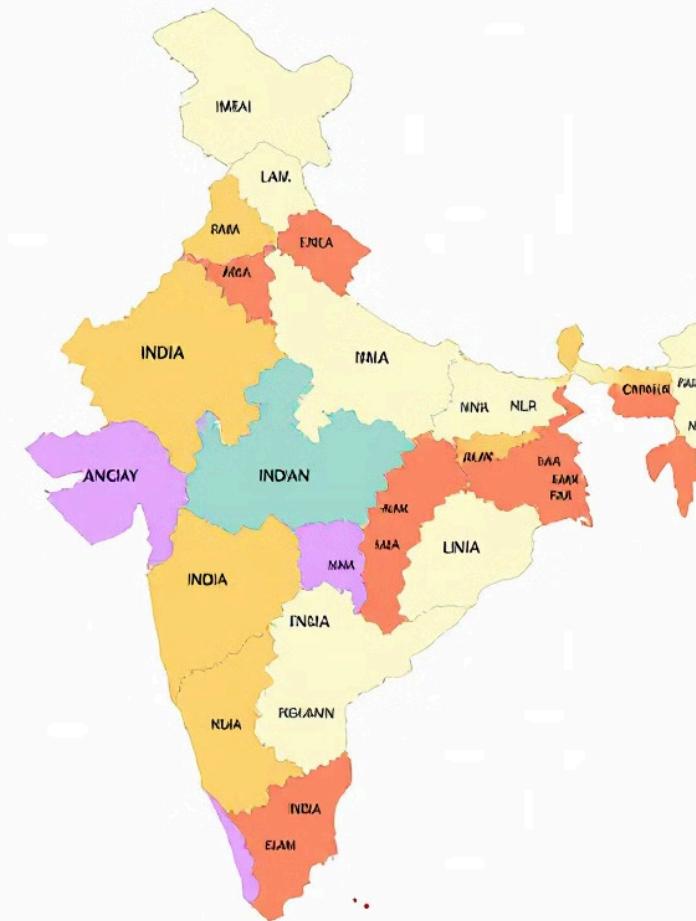
स्थिति को बनाए रखने के लिए एक समग्र लक्ष्य और जनसंख्या-प्रति-सीट मानक स्थापित करने के बाद सीट आवंटन में अनुपातिक वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।

जनसांख्यिकीय प्रदर्शन

प्रभावी नीतियों और शासन के माध्यम से बेहतर जनसांख्यिकीय संकेतकों को प्राप्त करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करना।

जनसंख्या आकार को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के एकमात्र मानदंड के रूप में आगे बढ़ने का समय आ गया है। कई वैकल्पिक दृष्टिकोण अधिक समान प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व मध्य मार्ग प्रदान करता है जो उच्च जनसंख्या वाले शहरी केंद्रों और कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों दोनों को प्रतिनिधित्व देता है।

States:
States colored size,
based in land area...



2 States – Land area

States is protection ant
allocational size

States population

A propotional
a propotional
parliameany

Map 3 States

States
colored ases

प्रति व्यक्ति मादिरापान



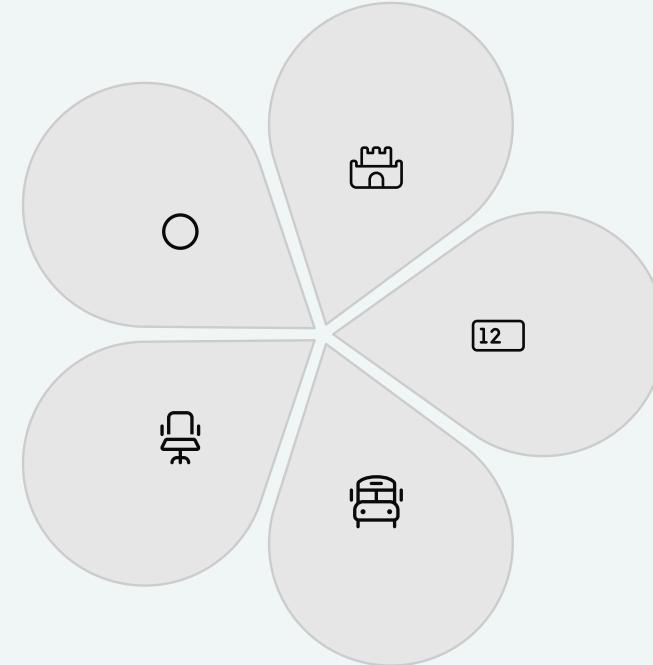
जनसंख्या-आधारित गणनाओं में एक महत्वपूर्ण मुद्दा "प्रति व्यक्ति मादिरापान" कहा जा सकता है - कच्चे जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करने की प्रवृत्ति जिसमें जनसंख्या की विशेषताओं पर विचार नहीं किया जाता। यह दृष्टिकोण असमान जनसंख्याओं को समान मान लेता है, जिससे भ्रामक तुलनाएं और अनुचित मानकीकरण होता है।

यह समस्या सीमांकन से परे SDG वातावरण में भी व्याप्त है, जहां सूचकांक प्रति व्यक्ति मापदंडों का उपयोग करके बिना जनसंख्या संरचना के अंतरों पर विचार किए उत्पन्न किए जाते हैं।

जनसंख्या विशेषताओं की जटिलता

लिंग
लिंग अनुपात और प्रतिनिधित्व राज्यों में
काफी भिन्न हैं

आर्थिक स्थिति
आय असमानताएं अलग-अलग
नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता
होती है



जनसंख्या एक सरल मात्रा से कहीं अधिक है। प्रस्तावित सीमांकन अभ्यास को लिंग और जाति-आधारित आरक्षण के भीतर सीट आवंटन पर विचार करना चाहिए। जनसंख्या की विशेषताएं और संरचना आवश्यकताओं, अधिकारों और विशेषाधिकारों का आकलन करने में महत्वपूर्ण हैं।

जाति

जाति-आधारित आरक्षण राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है

आयु वितरण

विभिन्न आयु संरचनाएं विभिन्न आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं पैदा करती हैं

शैक्षिक स्तर

शैक्षिक उपलब्धि विकास की आवश्यकताओं को प्रभावित करती है

UPSC 2026-2027

Current Affairs

“SURE”

HWC Method

Rs.2000 per Month



जानिए, एक छोटी सी खबर से UPSC के 16 dimension कैसे कवर किए जाते हैं! 

जुड़िए Ojaank Sir के innovation current affairs "sure" से, सिर्फ 2000 रुपये प्रति माह में! 

 **LIMITED SEATS – FIRST COME, FIRST TRAINED**

Book Your Seat Now – Before It's Gone 

Ojaank IAS में Admission लेने लिए दिए गए link पर Click करके Form भरें -

<https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoejfjYTVnmIL69PIRmx/edit>

अधिक जानकारी के लिए तुरंत Call करें :- 8750711100/22/33/44/55

 Ojaank Sir के साथ सीधा Whatsapp से जुड़ें : 8285894079

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में वास्तविक चिंता

दक्षिणी राज्यों की चिंताएं

बेहतर जनसांख्यिकीय प्रदर्शन से प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में प्रगति को दंडित किया जा सकता है

राष्ट्रीय निर्णय लेने में राजनीतिक प्रभाव का नुकसान हो सकता है

उत्तरी राज्यों का ठब

उच्च जनसंख्या वृद्धि से प्रतिनिधित्व की आवश्यकताएं बढ़ती हैं

विकास चुनौतियों के लिए संसद में एक मजबूत आवाज की ज़रूरत है

जनसांख्यिकीय संक्रमण अभी भी प्रगति पर है

संघीय संतुलन पर खतरा

असंतुलित प्रतिनिधित्व सहयोगात्मक संघवाद को खतरे में डाल सकता है

संसाधन आवंटन अधिक विवादास्पद हो सकता है

राष्ट्रीय एकता के लिए समुचित राजनीतिक आवाज की ज़रूरत है

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में चिंता वास्तविक और महत्वपूर्ण है। दक्षिणी राज्य सीटें नहीं खोएंगे जबकि उत्तरी राज्य उन्हें प्राप्त करेंगे, ऐसे तर्कों को सुनना मजेदार है। वास्तविकता अधिक जटिल है, जिसमें सीमांकन अभ्यास में कई चिंताओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

सीमांकन अभ्यास में कई चिंताएं



प्रतिनिधित्व मानक

क्या प्रत्येक सीट का प्रतिनिधित्व 20 लाख की आबादी का औसत होना चाहिए, या क्या जनसंख्या वृद्धि के साथ लोक सभा के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए एक ऊपरी सीमा होनी चाहिए?



क्षेत्रीय वितरण

सीटों को क्षेत्रीय रूप से कैसे वितरित किया जा सकता है ताकि प्रतिनिधित्व को स्वीकार्य स्तर से बिगड़ा न जाए?



जनसांख्यिकीय विशेषताएं

जनसंख्या की संरचना और विशेषताओं को प्रतिनिधित्व के नियमों में कैसे शामिल किया जा सकता है?



संतुलन तंत्र

किस मध्यम मार्ग से जनसंख्या आकार और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन दोनों को न्यायसंगत तरीके से समायोजित किया जा सकता है?

सीमांकन अभ्यास कई जटिल चुनौतियों का सामना करता है जिन्हें सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भारत के विविध राज्यों में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व बनाए रखते हुए जनसंख्या आकार और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन दोनों का सम्मान करने वाला संतुलन बनाना हमारे राष्ट्र के संघीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

जनसांख्यिकीय दृष्टियः आगे का रास्ता



गुणों की पहचान

जनसंख्या के सभी संभावित विशेषताओं को स्वीकार करें



विभिन्न वजन

विभिन्न कारकों पर उचित वजन लागू करें



संतुलित दृष्टिकोण

विविधता और समानता का सम्मान करने वाला समाधान लागू करें

जनसंख्या के जनसांख्यिकीय पठन में सभी संभावित विशेषताओं और गुणों को पहचानना शामिल है ताकि जनसंख्या गणना में शामिल होने वाले तुलनात्मक संरचनाओं पर उचित वजन दिया जा सके। जनसंख्या प्रतिनिधित्व और आवंटन के मुद्दों पर एक मात्र मुख्य गिनती से परे है, हालांकि यह आम व्यवहार में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इसलिए, जनसांख्यिकीय दृष्टि ही प्रचलित बहुसों और विवादों को हल करने का कुंजी है। जनसंख्या गणना को एकमात्र मानक के रूप में सोचने से परे जाकर, भारत एक अधिक संवेदनशील, न्यायसंगत दृष्टिकोण विकसित कर सकता है जो इसके संघीय चरित्र को बढ़ाव देता है और सभी दाज्यों की प्रगति और ज़रूरतों का सम्मान करता है।

Follow Ojaank Sir



IAS with Ojaank Sir



Ojaank_Sir



IAS with Ojaank Sir

Free PDF Content

पाने के लिए अभी JOIN करें



8285894079



8285894079

👉 ऐसी ही UPSC Special Current News PDF के लिए Visit करें हमारी Official Website : www.ojaank.com

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link :

<https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine>

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link : <https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine>